Steps to Compensate Headquarters Employees of I.T.D.C for rise in Prices

*568. DR. LAXMINARAIN PANDEYA

SHRI DHAMANKAR·

Will the Mmister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question Nos 2136 and 1601 on the 7th April, 1972 and the 26th May, 1972 respectively and state what steps the India Tourism Development Corporation has taken to compensate the Headquarters employees of India Tourism Development Corporation for rise m prices during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR SAROJINI MAHISHI)· The Headquarters employees of the India Tourism Development Corporation received bonus for the years 1970-71 and 1971-72 at 10 per cent.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न भिन्न था । मैं ने पूछा था कि प्राइस इन्डेक्स में वृद्धि के अनुरूप हैडक्वार्टर के कर्मचारियो को कामपेन्सेशन के रूप मे क्या दिया गया है । मंत्री महोदय के कहा है कि उन को बोनस दिया गया है । मेरा निवेदन है कि आई० टी० डी० सी० कम्पनी एक्ट के अन्तगर्त राजिस्टर्ड है और वह एक कामर्शल अडरटेकिंग है । उस लिए उन के कर्मचारियो को बोनस देना तो अनिवार्य है । अगर उन को बोनस दिया जाता है, तो इस में कोई आबलिगेशन नही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइस इन्डेक्स में वृद्धि को मीट करने के लिए उन को किस प्रकार काम्पेन्सेट करने का प्रयत्न किया गया है ।

डा० सरोजिनी महिषी : उन को कम्पेन्सेट करने का प्रयत्न किया गया है । हेडक्वार्टर मे काम करने वाले एक एप्लाई को अशोका होटल या जनपथ होटल मे उसी ग्रेड में काम करने वाले एप्लाई की तुलना मे डीयरनेस एलाउंस, हाउस रेंट एलाउंस और सिटी काम्पेन्सेटरी एलाउंस के रूप मे ज्यादा पैसा मिल जाता है ।

डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय क्या यह सही है कि जब 1970 मे प्रथम अन्तरिम रिलीफ दिया गया था, तब से इन दो वर्षो मे प्राइस इन्डेक्स मे काफी वृद्धि हुई है, लेकिन उस के बावजूद उन कर्मचारियो का 1970 मे जो वेतन था, उस मे और आज के वेतन मे कोई अन्तर नही है ।

डा० सरोजिनी महिषी · माननीय सदस्य की इनफर्मेशन ठीक नही है । अगर उन कर्मचारियो के वेतन मे नही, तो उन के डीयरनेस एलाउंस, हाउस रेंट एलाउंस और सिटी काम्पेन्सेटरी एलाउंस, मे काफी वृद्धि हो चुकी है । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वेज बोर्ड की नियुक्ति की थी, उसके 1968 के एवार्ड के अनुसार डीयरनेस एलाउंस प्राईस इन्डेक्स के साथ जुडा है और इस लिए उस मे काफी परिवर्तन होता रहता है ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय मैं ने यह पूछा है कि क्या यह सही है कि 1970 मे, जब की प्रथम अन्तरिम सहायता किया गया था, और उस जो कर्मचारियों को वेतन था, उन को वही वेतन आज भी है मिल रहा है ।

डा० सरोजिनी महिषी : यह सही नहीं है।

श्री रामरतन शर्मा : मंत्री महोदय ने हाउस रेंट की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत हाउस रेंट एलाउंस मिलता है, यदि नहीं, तो उन के हॉटल एमालुमेंटस में 25 प्रतिशत हाउस रेंट एलाउंस क्यों जोड़ा जाता है।

डा० सरोजिनी महिषी : 25 प्रतिशत हाउस रेंट एलाउस सभी को नहीं मिलता है। जो रिसीट प्रोड्यूस करते हैं, उन्ही को मिलता है। जो रिसीट प्रोड्यूस नही करते है, उन को आम तौर पर 15 प्रतिशत हाउस रेंट एलाउंस दिया जाता है।

Arrears of Taxes against Foreign Firms

+

*569. SHRI JAGANNATH MISHRA: SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a large amount of tax arrears remain outstandmg against a number of foreign firms functioning in India;

(b) if so, the steps proposed to recover tax arrears from such firms, especially from those which have wound up their business in India by now; and

(c) the names of the firms against whom tax arrears are outstanding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) to (c). The term 'foreign firm' has not been defined in the Income-tax Act. Income-tax statistics are not maintained separately in respect of Indian and foreign assessees. However, 'foreign company' has been defined in Section 80B(4) of the Income-tax Act, 1961 as a company which is not a domestic company. Information regarding foreign companies against whom income-tax arrears of Rs. 50,000 or above were outstanding as on 31st March, 1972 has been collected. These particulars show that there are 20 such companies. The names of these companies, the amounts of income-tax outstanding as on 31st March, 1972 and the steps already taken and being taken for recovering the arrears are given in the Statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library, See* No. Lt-4141/72.]

Out of these 20 companies, only two companies, namely M/s. F. C. Oslar Limited and M/s. Amco Furnace Construction Ltd. have wound up their business in India. Arrears in respect of four other companies have since been reduced to 'nil'.

SHRI JAGANNATH MISHRA: May I know from the hon. Minister whether foreign firms running in arrears have sought the Government of India's permission for winding up their business in India and why they were allowed to do so before realisation of the arrears?

SHRI K. R. GANESH: I have no such information as yet.

SHRI JAGANNATH MISHRA: May I know whether with the Simla agreement and the consequent normalisation of relations with Pakistan the question of recovery of tax arrears in regard to Pakistan Airlines, Pakistan shipping lines and Mohammedi steamship Co. has been taken up and if so with what results?

SHRI K. R. GANESH: The arrears of the three Pakistani companies are awaiting DIT relief and when they are in a position to get proper documents from the Pakistani authorities steps will be taken.